POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 10

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले एक दशक में राजनीतिक दलों की छवि में भारी गिरावट आई है। लोग राजनीतिक दलों को सबसे भ्रष्ट मानने लगे हैं। इस सच्चाई को अन्तरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट ने भी उजागर किया है।

सर्वे में देश के 71 फीसदी लोगों ने राय जताई है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि हुई है। अफसोस यह है, जनता की इस धारणा के बावजूद, सुधार लाने के बजाय सभी दल उल्टी दिशा में बहना पसंद कर रहे हैं।

राजनीतिक दलों पर आरटीआई कानून लागू करने का फैसला हो या अपराधी व दागी नेताओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आमजन ने देखा है किस प्रकार सभी दलों में इससे बेचेनी बढ़ गई। किस तरह संसद में सभी दल इन निर्णयों के खिलाफ एकमत हो गए और आखिर इन फैसलों को उलटने के लिए कानूनों में संशोधन तक कर दिया गया। क्यों सभी दल जनता के प्रति जवाबदेह होना नहीं चाहते?

चुनाव नजदीक है! यही दल तरह-तरह की घोषणाओं का शर्बत पिला कर जनता को भ्रमित करने में लगे हैं। क्या की गई सभी घोषणाओं पर ईमानदारी से अमल होता है? गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली-पानी रोजगार आदि सभी घोषणाएं भ्रष्टाचार से क्यों जुड़ जाती हैं?

इस बार हर मतदाता को गहन विचार कर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। केवल स्वच्छ छवि और ईमानदार जनप्रतिनिधि ही संसद और विधान सभा में पहुंचे, इसके लिए संकल्पित होना है।

बिना वकील, बिना खर्च पाएं न्याय

आम आदमी को शीघ्र, निःशुल्क और सरलता से न्याय दिलाने के मकसद से राज्य के जिला स्तर और तहसील स्तर पर लोक अदालतें संचालित हैं। इनमें दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है। इन अदालतों द्वारा जन हित के मामलों पर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।

- इन अदालतों का संचालन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन में मामला ले जाने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं होती न ही किसी तरह की कोर्ट फीस लगती है।
- लोक अदालत में पीड़ित व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत करना काफी सरल है। परिवाद का पंजीयन हो जाने के बाद अदालत दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाती है। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। आवश्यक प्रलेख भी मंगाए जाते हैं।

- इन अदालतों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को खासतौर से आपसी बातचीत, समझौते और राजीनामे से निस्तारित किया जाता है। अदालत की खर्चीली और लम्बी प्रक्रिया से बचने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को सर्वोपरि माना जाता है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती, क्योंकि मामला सुलह से निपटाया जाता है। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

चिकित्सक पर एक लाख रुपए का जुर्माना

झालावाड़ जिले के ख्वाजू मोहम्मद ने एस.के.चिकित्सालय के चिकित्सक इकबाल खान के खिलाफ उपभोक्ता मंच, झालावाड़ में परिवाद दर्ज कराया। इस परिवाद में ख्वाजू मोहम्मद ने मंच को बताया कि उन्होंने 20 फरवरी, 2011 को अपनी 7 माह से गर्भवती पत्नी नजमा को उपचार के लिए एस.के. अस्पताल में भर्ती कराया था। इस निजी चिकित्सालय में उनकी पत्नी का उपचार चिकित्सक इकबाल खान ने किया। इसके बदले में उनसे 30 हजार रुपए वसूले गए। लेकिन गलत उपचार के कारण उनकी पत्नी के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। उन्होंने मंच के सामने अपनी पत्नी और गर्भस्थ शिशु के इलाज में चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही को उजागर किया।

मंच ने सुनवाई पर ख्वाजू मोहम्मद के बयानों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही और गलत उपचार को गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने चिकित्सक इकबाल खान को आदेश दिया कि वह ख्वाजू मोहम्मद को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में अदा करे।

'कट्स' सर्वेक्षण - 2013

प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी राजस्थान के लोगों की पहली पसंद

राजस्थान के 64 फीसदी लोग नरेन्द्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि केन्द्र की वर्तमान यूपीए सरकार के काम-काज से वे संतुष्ट नहीं है। यह तथ्य कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा राजस्थान में कराए गए 'चुनाव सर्वे, 2013' में सामने आया है।

यह सर्वे चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय व राजस्थान सरकार के कामकाज का आकलन करने और विभिन्न समस्याओं पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से, प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया। सर्वे में राज्य के सभी जाति, समुदाय व वर्गों के लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है।

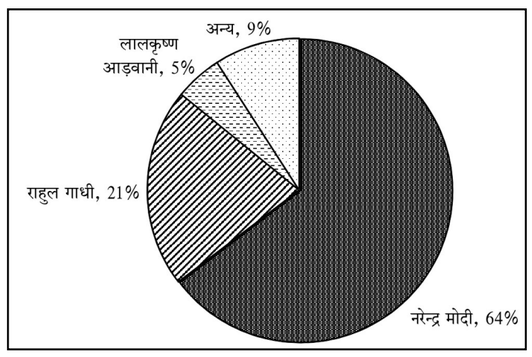

भाजपा के बहुमत की उम्मीद

राज्य के लोगों ने राजस्थान विधान सभा में भी परिवर्तन की इच्छा जताई है। प्रदेश के 57 फीसदी लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल को सामान्य दर्जे का माना है।

प्रदेश के 64 फीसदी लोगों की अगले मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे पहली पसंद है तथा 61 फीसदी लोगों ने यह उम्मीद भी जताई है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा।

भ्रष्टाचार देश की प्रमुख समस्या

सर्वे के विश्लेषण में यह सामने आया कि प्रदेश के 44 फीसदी लोग भ्रष्टाचार और महंगाई को वर्तमान केन्द्र सरकार की देन मानते हैं।

लोगों ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व आर्थिक नीतियों की असरदार क्रियान्विति नहीं होने को खास कारण माना है। लोग भ्रष्टाचार को देश की प्रमुख समस्या मानते हैं। लोगों का सोचना है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है।

- यह भी आया सामने -

- *राजस्थान के मात्र 21 फीसदी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं।*
- *केन्द्र सरकार के अब तक के कार्यकाल को प्रदेश के 09 फीसदी लोगों ने सफल, 48 फीसदी ने सामान्य, 41 फीसदी ने असफल बताया।*
- *प्रदेश के 16 फीसदी लोग राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल को सफल, 57 फीसदी सामान्य और 25 फीसदी असफल मानते हैं।*
- *प्रदेश में मुफ्त दवा और जांच योजना से 39 फीसदी लोग संतुष्ट हैं, वहीं 51 फीसदी लोग इसे गुणवत्ता पूर्ण सेवा नहीं मानते।*

स्कूलों में शिक्षकों की कमी

राज्यपाल मारग्रेट अल्वा ने प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में 70 हजार स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों के लिए आठ हजार स्कूलों में पेयजल सुविधा और 15 हजार स्कूलों में टॉयलेट सुविधा नहीं है।

उन्होंने कहा कि गांवों में शिक्षक नौकरी नहीं करना चाहते। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का प्रतिशत भी बहुत अधिक है। शिक्षामंत्री बृज किशोर शर्मा ने भी माना है कि प्राईमरी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है।

सरकार मुफ्त बांटेगी मोबाइल, टेबलेट

केन्द्र की यूपीए सरकार अपने चुनावी पिटारे से एक और बंपर स्कीम निकालने जा रही है। इस नई योजना के तहत गरीबों को ढाई करोड़ मोबाइल और 90 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे।

योजना पर 7860 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस स्कीम के तहत गरीबों को दिए जाने वाले मोबाइल में दो साल के लिए फ्री कनेक्शन होगा। इसके लिए उनसे एकमुश्त 300 रुपए लिए जाएंगे।

बिजली की तरह तय होंगी पानी की दरें

राज्य में जल्द ही जल विनियामक प्राधिकरण बनेगा। यह प्राधिकरण राज्य की कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी की दरें तय करने का काम करेगा।

राज्य विधानसभा में इस संबंध में राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पारित कर दिया गया है। इससे अब बिजली की तरह पानी की दरें तय की जाएंगी। प्राधिकरण जनता की राय के बाद ऐसी दरें निर्धारित करेगा, जिससे उपभोक्ता पर ज्यादा भार न पड़े।

सरकार ने किया दागियों का बचाव

आखिरकार दागी सांसदों व विधायकों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब अपराधिक सांसदों व विधायकों की सीट सुरक्षित रहेगी। वे जेल में रहते चुनाव भी लड़ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में ही बदलाव कर दिया। क्योंकि सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एकजुट थीं। कैबिनेट ने इस संशोधन पर मुहर लगा दी है।

पेंशन-साड़ी और कंबल पाओ

अब तक विपक्ष राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सरकार सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए पेंशन और साड़ी-कंबल बांट रही है। लेकिन अब सामाजिक न्याय विभाग व्यवस्था करने जा रहा है कि प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति कभी भी अपने दस्तावेज लेकर आता है और वह पात्रता रखता है, तो उसे तत्काल पेंशन, साड़ी-कंबल जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

आरटीआई से परहेज क्यों?

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने राजनेताओं पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चार साल पहले संसद में जनता से पूछे बिना सूचना का अधिकार कानून में संशोधन नहीं करने का भरोसा दिलाया था, अब खुद के लिए वे इससे क्यों पीछे हट रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीतिक दल आरटीआई से क्यों डर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा से मिलेगी भूख से निजात?

खाद्य सुरक्षा आध्यादेश से निर्धन व कमजोर वर्ग को भूख से निजात नहीं दिलाई जा सकेगी, 34 फीसदी लोगों का यह मानना है, जबकि 40 फीसदी लोग मानते हैं कि इससे कुछ हद तक ही गरीबों को फायदा मिल सकेगा। अभी भी 81 फीसदी लोग देश की राशन वितरण व्यवस्था से ही संतुष्ट नहीं है।

लोगों का यह भी मानना है कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली निर्धन वर्ग को आगे बढ़ाने के बजाय कमजोर करेगी। लोग कामधंधे व श्रम से विमुख हो जाएंगे। इसके बजाय गरीबों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति व रोजगार के लिए ऋण जैसी सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।

देश में आकंठ भ्रष्टाचार

ग्राम गदर का पिछला अंक पढ़ा। ग्राम गदर की पीड़ा सारे जग की पीड़ा है। देश में चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय स्तर की, आज के हालात बयान करते हैं कि सभी पार्टियों में कहीं न कहीं गंदगी रची बसी है। देश इससे अपमानित हो रहा है। कोई भी पार्टी हो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। योजनाओं की क्रियान्विति में कर्त्तव्य बोध की कमी और भ्रष्टाचार साफ दिखाई देता है।

- डॉ. के.एम शर्मा, पाली

योजना प्रभावी रूप से लागू हो

खाद्य सुरक्षा आध्यादेश को अगर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो ठीक होगा, वर्तमान में भी हमारे देश में ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, परन्तु उनके परिणाम योजना अनुरूप नहीं है। लोग चाहते हैं नई सरकार भ्रष्टाचार, जातिवाद और भाई-भतीजेवाद से मुक्त हो ताकि राज्य का आधारभूत विकास संभव हो सके।

- गोरधनराम बामणिया, बाड़मेर

निरीक्षण व्यवस्था हो कारगर

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ योग्य व पात्र व्यक्तियों को पूरी तरह और सही तरीके से मिले। निरीक्षण की व्यवस्था कारगर तरीके से हो सके ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार को रोका जाए। बेरोजगारी व महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है। सरकार पहले उचित कदम उठाकर इन समस्याओं को दूर करे।

- सुरेन्द्र कुमार, हनुमानगढ़

गरीबों को मिलेगा पोषित भोजन

खाद्य सुरक्षा का मकसद आम आदमी को पोषित आहार उपलब्ध कराना है। यह अच्छी योजना है। इसे सही रूप में लागू किया जाए। जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जाए। अपेक्षा है आने वाली सरकार आम जनता के हित में काम करे। गरीब व असहाय लोगों को जरूरत के आधार पर लाभ देगी।

- आरिफ हुसैन जेड़, कोटा

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर